नव भारत
राष्ट्रीयता का प्रहरी 1934 से

जनता के बीच भाजपा

प्रधानमंत्री के 76वें जन्मदिन पर आज से सेवा संकल्प अभियान

नवभारत न्यूज नई दिल्ली, 16 सितंबर. भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सत्ता से लेकर संगठन स्तर तक संपूर्ण रूप से मैदान में दिखेगी. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 76वें जन्मदिन और उनके सार्वजनिक संवैधानिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 पार्टी का देशव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरु होगा.

यह अभियान बूथ स्तर तक चलेगा. जिसमें संगठन के मुखिया से लेकर कार्यकर्ता तक, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर भाजपा शासित सभी राज्यों की सरकारें शामिल होंगी. पार्टी इस अभियान को लेकर पिछले दो माह से तैयारी कर रही है. इसका मुख्य उद्देश्य जनता तक केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है. साथ ही युवाओं के बीच पार्टी की विचारधारा को धार देने के साथ ही उन्हें जोड़ना है. इसे सफल बनाने को लेकर पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई. इस उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य एक माह लंबे चलने वाले कार्यक्रमों की अंतिम रूपरेखा की समीक्षा करना और बूथ स्तर तक इसके सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था.

तावड़े को अहम जिम्मेदारी

बैठक में संगठन के शीर्ष नेतृत्व सहित राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, जिन्हें इस पूरे राष्ट्रव्यापी अभियान के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर देखरेख की कमान सौंपी गई है, विशेष रूप से उपस्थित थे. उनके साथ ही पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों, विभिन्न राज्यों के संगठन प्रभारियों, राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और सूचना तंत्र से जुड़े प्रमुख नेताओं ने भी इस मंथन में हिस्सा लिया. इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और मुख्यमंत्रियों को भी वर्चुअली माध्यम से इस बैठक की रणनीतियों से अवगत कराया गया.

जन-आंदोलन की तैयारी

बैठक के दौरान नेताओं ने इस बात पर विशेष बल दिया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले इस सेवा संकल्प अभियान को मात्र एक राजनीतिक आयोजन न बनाकर एक जन-आंदोलन का रूप दिया जाए. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, जिससे पिछले वर्षों में गरीबी से बाहर आए लगभग 25 करोड़ लाभार्थियों को इस अभियान के केंद्र में रखा जाए.

सेमीकॉन इंडिया उद्घाटन करेंगे पीएम

नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे. 600 से अधिक कंपनियां शामिल होंगी और 52 देशों के प्रतिनिधियों के पहुंचने की उम्मीद है. करीब 50 हजार लोग प्रदर्शनी और सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं. कार्यक्रम में 400 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी और 150 से ज्यादा वक्ता शामिल होंगे.

कर्तव्य पथ पर सवा लाख दीये

प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर 'आशीर्वाद का दीया' अभियान के अंतर्गत एक विशेष दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित किया गया है. शाम 7 बजे कर्तव्य पथ पर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों आदि द्वारा एक लाख दीये प्रज्वलित किए जाएंगे.

रैपिडो पर लगा 10 लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 'रैपिडो' चलाने वाली कंपनी 'रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड' पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सीसीपीए ने यह जुर्माना गुमराह करने वाले विज्ञापनों, अनुचित बिज़नेस प्रैक्टिस, अनुचित अनुबंध और 'डार्क पैटर्न' जैसे राइड कन्फर्म होने से पहले ही राइडर्स को ज्यादा पैसे देने के लिए प्रोत्साहित करना, ऐसे आरोप जांच में साबित होने के बाद लगाया है. इस जांच का मकसद राइड से पहले टिपिंग और डायनामिक प्राइसिंग से जुड़े तौर-तरीकों को एग्जामिन करना था.

अब 25,000 के बेसिक तक कटेगा पीएफ

सरकार ने 12 साल बाद बढ़ाई वेतन सीमा

नवभारत न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली, 16 सितंबर. केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ईपीएफओ के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.

यह फैसला बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुआ. इसके बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी. इस फैसले से 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आ सकते हैं.

करीब 12 साल बाद सरकार ने इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का फैसला लिया है. अभी 15,000 रुपये से ज्यादा मासिक वेतन वाला कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफ कवरेज के दायरे में नहीं आता था. अब 25,000 रुपये तक प्रति माह वेतन पाने वाले कर्मचारी ईपीएफ के दायरे में आएंगे.

ईपीएफओ के दायरे में 8 करोड़ योगदानकर्ता

ईपीएफओ दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक है. ईपीएफओ के तहत करीब 7.98 करोड़ योगदान करने वाले सदस्य हैं और करीब 7.68 लाख योगदान करने वाले प्रतिष्ठान इससे जुड़े हैं. ईपीएस के तहत करीब 82 लाख पेंशनभोगियों को पेंशन लाभ मिलता है. ईडीएलआई योजना ईपीएफ सदस्यों को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है.

पेंशन और इंश्योरेंस का भी लाभ
कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा

ईपीएफ तहत कर्मचारियों को लागू योजना के प्रावधानों के अनुसार रिटायरमेंट सेविंग, ईपीएस के तहत पेंशन सुरक्षा और ईडीएलआई के तहत बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा. इस फैसले से सरकार के खर्च में भी बढ़ोतरी होगी. सरकार का वार्षिक खर्च करीब 11,339 करोड़ रुपये होगा. फिलहाल सरकार करीब 10,250 करोड़ रुपये सालाना बजटीय सहायता देती है. पांच साल की अवधि में अनुमानित कुल खर्च करीब 56,696 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.

बीजेपी विधायक ने वापस की पीएम के दोस्त को जमीन

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क भायंदर, 16 सितंबर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्कूल के साथी असगर अली वोरा को उनकी जमीन वापस मिल गई है. मीरा रोड के रहने वाले 81 साल वोरा ने पीएम मोदी से मिलकर आरोप लगाया था कि बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने भयांदर में उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है.

पीएम तक मामला पहुंचने के बाद बीएमसी के अफसर सक्रिय हुए और तत्काल दोनों पक्षों को बुलाकर मामला निपटाया. बैठक में नेता ने कहा कि वह विवादित जमीन का कब्जा छोड़ रहे हैं और उस प्लॉट के लिए मिली कंस्ट्रक्शन की मंजूरी भी सरेंडर कर रहे हैं. मेहता ने वोरा के खिलाफ पहले की गई अपनी शिकायत भी वापस ले ली है.

पीएम से मुलाकात के बाद अधिकारियों का एक्शन

भारत के युद्धपोत से भिड़ा पाकिस्तानी जहाज

विदेश मंत्रालय का कड़ा विरोध, तलब किया प्रभारी राजदूत

नवभारत न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली, 16 सितंबर. उत्तर अरब सागर में 15 सितंबर की शाम भारतीय और पाकिस्तानी नौसेना के जहाजों की आपस में टक्कर हो गई. पाकिस्तानी नौसेना के एक तेज रफ्तार जहाज ने भारतीय नेवी के युद्धपोत को टक्कर मार दी है. इस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

भारत के विदेश मंत्रालय ने सख्त रूख अपनाते हुए पाकिस्तान के प्रभारी राजदूत को तलब कर लिया है. घटना 15 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में हुई है.

घटना के बाद मामला सिर्फ समुद्री टक्कर तक सीमित नहीं रहा. भारत ने बुधवार को नई दिल्ली में पाकिस्तान के प्रभारी राजदूत साद वारैच को विदेश मंत्रालय में तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया है. भारत ने पाकिस्तानी नौसैनिक इकाई के व्यवहार को अस्वीकार्य और गैर-पेशेवर बताया है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे घटनाक्रम दोबारा न हों, इसके लिए दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का पालन जरूरी है. भारतीय युद्धपोत नियमित निगरानी मिशन पर था.

पाकिस्तान को सिखाया सबक

भारत ने पाकिस्तानी प्रभारी राजदूत से कहा कि वह संबंधित अधिकारियों तक यह संदेश पहुंचाएं कि सभी सैन्य इकाइयां समुद्र में जरूरी सावधानी बरतें और दोनों देशों के बीच लागू समझौतों का सम्मान करें. भारत ने यह भी कहा कि ऐसा करना भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है.

एक नजर में

यूपीआई चार्ज का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली. यूपीआई चार्ज मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही गया. देश की सर्वोच्च अदालत में बुधवार को एक याचिका दाखिल की गई है. इसमें वित्त मंत्रालय की 14 और 15 सितंबर की राजपत्र अधिसूचनाओं को रद्द करने की मांग की गई है. इन अधिसूचनाओं में 2000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने का ऐलान किया गया था.

चीन वापस पहुंचते ही जिनपिंग अस्पताल में

बिजिंग. चीनी लोकतंत्र पार्टी के चेयरमैन जी वानजुन के मुताबिक, भारत में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद चीन लौटे शी जिनपिंग को बीजिंग एयरपोर्ट से सीधे सैन्य हेलीकॉप्टर के जरिए 301 अस्पताल ले जाया गया. उनका दावा है कि जिनपिंग को अस्पताल में आपातकालीन उपचार दिया गया.

शरीयत के खिलाफ कानून नहीं मानेंगे: मदनी

नई दिल्ली. यूसीसी लागू करने के को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है. जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि देश संविधान से चलेगा या किसी राजनीतिक दल के वैचारिक एजेंडे से.मुसलमान ऐसा कोई कानून स्वीकार नहीं कर सकते, जो शरीयत के खिलाफ हो.

टेकऑफ करते ही फटा टायर

केबिन की छत गिरी, चीखते-चिल्लाते रहे यात्री

नवभारत न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली, 16 सितंबर. ईरान के मशहद से करमानशाह जा रहे सेपहरान एयरलाइंस का बोइंग 737 विमान एयरपोर्ट पर दुर्घटना का शिकार हो गया. विमान के टेकऑफ के साथ ही टायर फट गए और प्लेन के अंदर यात्रियों में हड़कंप मच गया.

दरअसल, विमान के लैंडिंग गियर का एक टायर फटकर अलग हो गया था. स्थिति को देखते हुए पायलटों ने इमरजेंसी घोषित की और विमान को वापस मशहद एयरपोर्ट ले आए.

बाल-बाल बचे विमान सवार

लैंडिंग के वक्त विमान के केबिन की छत का अंदरूनी हिस्सा अचानक यात्रियों के ऊपर आ गिरा. इस दौरान यात्री घबराकर चीखते हुए भी दिखाई दिए. हालांकि, इस घटना में राहत की बात यह रही कि किसी भी यात्री को चोट नहीं लगी. विमान के सुरक्षित रूप से लैंड करने के बाद सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया.

झीरम घाटी : 10 दोषियों को फांसी

27 लोगों की हत्या के मामले में 13 साल बाद एनआईए कोर्ट का फैसला

नवभारत न्यूज नेटवर्क रायपुर, 16 सितंबर. छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी नक्सली हमले के मामले में दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है. 27 लोगों की हत्या के मामले में एनआईए कोर्ट ने 13 साल बाद ये फैसला सुनाया है.

बुधवार को जगदलपुर स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया. 5 सितंबर 2026 को सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था. इसके बाद अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है. 25 मई 2013 को झीरम घाटी में हुए इस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके पुत्र दिनेश पटेल, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, उदय मुदलियार समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मी मारे गए थे.

झीरम मामले में अदालत ने दोषियों के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक धाराओं में दोषसिद्धि के बाद सजा सुनाई है.

25 मई 2013 को हुआ था झीरम का नरसंहार

25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा सुकमा से जगदलपुर लौट रही थी. दरभा क्षेत्र की झीरम घाटी में माओवादियों ने काफिले को घेरकर पहले विस्फोट किया और फिर भारी गोलीबारी की. इस हमले ने पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति को हिलाकर रख दिया था. कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं समेत बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई थी.

राहुल, सोनिया, लालू समेत कई नेता ईडी के टारगेट

पीएमएलए एक्ट के केस 2029 से पहले फैसलों तक पहुंचाने की तैयारी

नवभारत न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली, 16 सितंबर. प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए एक्ट के तहत दर्ज हाईप्रोफाइल मामलों में जांच तेज कर दी है. डायरेक्टर राहुल नवीन ने जोनल अफसरों को इसके निर्देश दिए हैं.

डायरेक्टर ने एक बैठक में आदेश दिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमों को तेजी से नतीजे तक पहुंचाया जाए, एआई के इस्तेमाल से बचते हुए पुख्ता सबूतों के साथ कोर्ट ट्रायल में केस फाइनल स्थिति पहुंचे.

नेताओं की बढ़ेगी मुश्किल

- 4कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड घोटाला केस
- 4लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाला केस
- 4झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची के बड़गाई जमीन फर्जीवाड़ा केस
- 4आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली शराब नीति घोटाला केस
- 4कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल-मैक्सिस केस

सजा दिलाने का लक्ष्य

जोनल चीफ से कहा कि अपने जोन में ऐसे कम से कम 10 हाई-प्रोफाइल केस की पहचान करें, जिन्हें 6 से 8 महीने के अंदर अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है. निदेशक ने अपने अफसरों को निर्देश दिए कि ट्रायल शुरू होने से पहले तैयारियों को पुख्ता करके रखें. जो मुकदमे 6 महीने से ज्यादा संज्ञान लिए जाने का इंतजार कर रहे हैं, उनकी हर महीने समीक्षा करें. जो मामले 10 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनकी विशेष तरह से निगरानी करें.

सियासत नई टीम की घोषणा से पहले राहुल और प्रियंका नेताओं का कर रहे वन टू वन इंटरव्यू

कांग्रेस में जल्द ही होगा व्यापक फेरबदल

नवभारत न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली, 15 सितंबर. पिछले कई महीनों से संगठन सृजन के तहत राष्ट्रीय स्तर पर जमीनी यानी पंचायत स्तर पर सांगठनिक ढांचे को पुनर्गठित करने में जुटी कांग्रेस पार्टी इन दिनों केन्द्रीय संगठन को भी बदलते राजनीतिक दौर के लिए तैयार करने में जुटी है.

इसी सिलसिले में पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के नेतृत्व में एक विशेष समीक्षा बैठक की गई. इस बैठक में पार्टी के वर्तमान में कार्यरत सभी 64 एआईसीसी सचिवों को अलग-अलग बैच में बुलाकर उनके कामकाज की कड़ी सांगठनिक समीक्षा की गई. इस प्रक्रिया के माध्यम से पार्टी नेतृत्व द्वारा प्रत्येक राज्य के सांगठनिक ढांचे, स्थानीय चुनौतियों, आगामी चुनावों की तैयारियों और प्रभारियों के कामकाज का व्यक्तिगत स्तर पर विस्तृत फीडबैक लेने का प्रयास किया गया. इस व्यावहारिक समीक्षा के बाद यह संकेत मिल रहे हैं कि संगठन में बड़े पैमाने पर सर्जरी होने वाली है, जिसके तहत लचर प्रदर्शन करने वाले लगभग 50 प्रतिशत मौजूदा सचिवों को उनके पदों से हटाया जा सकता है. क्योंकि पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब केवल कागजों पर या दिल्ली में रहकर राजनीति करने वाले नेताओं को संगठन में जगह नहीं मिलेगी.

अब सचिवों को प्रभार वाले राज्यों में कम से कम पंद्रह दिन रहना होगा. उल्लेखनीय है कि पिछले दो सप्ताह में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा नए और युवा चेहरों को संगठन में शामिल करने के लिए करीब 130 से 150 संभावित उम्मीदवारों का व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया गया था.

मोंडेगर कैफे का लाइसेंस सस्पेंड

मुंबई. महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई के मशहूर कैफे मोंडेगर पर कार्यवाही करते हुए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है. एफडीए की जांच में फूड सेफ्टी और साफ-सफाई में गंभीर कमियां पाई गईं. कैफे मोंडेगर के अलावा तीन और रेस्टोरेंट पर कमिश्नर तुकाराम मुंडे की टीम ने कार्रवाई की है.एफडीए ने एक बयान में कहा कि कमियों में गर्म खाने को 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और ठंडे खाने को 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे स्टोर न करना शामिल था. जांच के दौरान सेफ्टी और साफ-सफाई में भी गंभीर कमियां पाई गईं.